LOK SABHA

Saturday, May 12, 1962/Vaisakha 22, 1884 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

BUSINESS OF THE HOUSE

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha): With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 14th May will consist of:—

(1) Consideration of any item of business carried over from today's Order Paper.

(2) Discussion and voting on the Demands for Grants relating to the Ministries of Mines and Fuel, Steel and Heavy Industries, Irrigation and Power, and Transport and Communications.

11.01 hrs.

RE. PASSES FOR SWEARING IN CEREMONY OF PRESIDENT AND VICE-PRESIDENT

Mr. Speaker: Before we take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Community Development and Co-operation, there is one thing that I want to refer to.

Certain hon. Members of the House had written to me yesterday expressing some resentment that they had not been given passes for their wives to attend the function that would be held inside the Parliament House tomorrow. Rather that was a very strongly worded letter.

The difficulty has been this. I have discussed that with the Home Ministry. The difficulty really is that the capacity of the Hall is very limited. But, anyhow, all those hon .Members who had applied would be given those passes; just in a few minutes' time, they would get them. If there are a few more who want those passes, they might just send in the applications and they would also be provided. There ought not to be any difficulty. But it must be appreciated that the capacity of the Hall is limited and, therefore, everyone cannot be given a pass, if he desires. We also should co-operate with the other authorities, namely the Home Ministry, so that this function might go on quite smoothly as we desire.

11.03 hrs.

*DEMANDS FOR GRANTS—*contd.

MINISTRY OF COMMUNITY DEVELOPMENT AND CO-OPERATION—*contd.*

Mr. Speaker: The House will now take up discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Community Development and Co-operation.

Shri D. N. Tiwary.

Shri Subodh Hansda (Jhargram): What about my calling-attention-notice?

Mr. Speaker: The hon. Member will see that if in the beginning it cannot be raised, it can be taken up later, if it has not been rejected already. The

*Moved with the recommendation of the President.

[Mr. Speaker]

hon. Member will get the information. He should have some patience.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्यूनिटी डेवेलपमेंट मंत्रालय को दाद देता हूं बहुत सुन्दर रिपोर्ट पेश करने के लिये । रिपोर्ट को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि सब कुछ अच्छा है और सुन्दर है । लेकिन ऐक्चुअल फैक्ट्स दूसरे हैं और रिपोर्ट में जो कुछ कहा गया है वह दूसरा है । मैं मानता हूं कि रिपोर्ट तैयार करने में विज्ञता हासिल की है और रिपोर्ट अच्छा तैयार का है । लेकिन इससे अच्छा होता कि रिपोर्ट वास्तविक स्थिति को देखते हुए होता । खैर, जो कुछ भी हो, रिपोर्ट्स तो अच्छी मिलती हैं, वह भले ही फैक्ट्स हों या न हों, पिक्चर रोजा हो या डार्क हो इसमे तो रोजा पिक्चर ही दिखलाई गई है ।

कम्यूनिटी डेवेलपमेंट का असली मकसद यह है कि विलेज लेबल पर लीडरशिप पैदा की जाय । विलेजेज की इनडेटेडनेस को दूर करके उनको सेल्फ सपोर्टिंग बनाया जाय । इस रिपोर्ट को पढ़ने से ज्ञात नहीं होता है कि इन उद्देश्यों को कहां तक पूरा किया जा सका है । जहां तक विलेज इनडेटेडनेस का सवाल है, कहीं भी इस रिपोर्ट में नहीं है कि पहले कितनी इनडेटेडनेस थी और इन दस वर्षों में, जब से कि यह कम्यूनिटी डेवेलपमेंट चल रहा है, उन गांवों मे कितनी इनडेटेडनेस कम हुई । मेरी समझ में विलेजेज की इनडेटेडनेस बढ़ती जा रही है । कुछ सरकारी कर और महाजनों का कर, और जिसको हम लोग सस्पेंस ऐकाउन्ट या हिन्दी में हथफेर कहते हैं उस तरह से रुपये का विलेजर्स के कन्धों पर भार अधिक होता जा रहा है । वह कैसे दूर होगा या दूर भी होगा या नहीं । क्या इनको अपना सब कुछ बेच बाच कर कर्जा अदा करना पड़ेगा ? इसमें इसका कोई आभास नहीं मिलता ।

दूसरा सवाल है कि वे कितने सेल्फ सपोर्टिंग हो सके हैं, विलेजर्स कहां तक अपने पैरों पर खड़े हो सके हैं इस का भी कोई आभास नहीं है । पंचायतें हुईं, कोआपरेटिवज कायम करने की कोशिश की जा रही हैं । जो गरीब तबके के लोग हैं उनके धन्धे को चलाने के लिये कोआपरेटिव्ज होती हैं, लेकिन १०० या ५० रुपये कर्ज दे देने से उनका काम चल नहीं सकता है । उनके पास साधन नहीं हैं और खर्च अधिक रहता है । उसके लिये क्या उपाय किया जा रहा है, यह भी रिपोर्ट में साफ नहीं है ।

गत दस वर्षों मे जो कम्यूनिटी डेवेलपमेंट चले उनमें करोड़ों रुपये खर्च हुए । यहां तक कि इस फाइव इयर प्लान में भी ३१४ करोड़ रुपये का प्राविजन है । कम्यूनिटी डेवेलपमेट की रिपोर्ट के पेज ६ पर हम देख सकते हैं । अगर इस खर्च को व्यक्तिगत आधार पर हर आदमी को बांट दें तो एक व्यक्ति पर करीब १० या १२ रु० आते हैं । एक फैमिली के ऊपर करीब ६० रु० आता है, अगर पांच आदमियों की फैमिली मानी जाये । आज जो इस विभाग का पैराफर्नेलिया है वह इतना खर्चीला है, इतना टाप हैवी है कि इस रुपये का फायदा लोगों को बहुत कम पहुंचता है । यदि हर फैमिली को ६० रु० वैसे ही दे दिया जाय तो शायद वह अपना भला ज्यादा कर सकते हैं बजाय उसके जो कि गवर्नमेंट कर रही है । एक एक कम्यूनिटी डेवेलपमेट ब्लाक पर १२ लाख रु० के लगभग खर्च होते हैं । उसमें स्टाफ पर कितना खर्च होता है, मकानों पर कितना खर्च होता है, टी० ए० पर कितना खर्च होता है, और दूसरे मद पर कितना खर्च होता है, मिड्ल मैन से लेकर लोगों तक जो पैसा जाता है, उसका आप अन्दाजा लगाइये ।

सामुदायिक विकास पंचायती राज और सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री

ब० सू० मूर्ति) : इस में मिड्स मैन कहां से आ जाता है ?

श्री द्वा० ना० तिवारी : मिड्लमैन का वर्णन मैं करूं तो शायद आप दंग रह जायेंगे । मिड्लमैन वह होते हैं जो किसी रुपये लेने वाले की पैरवी करते हैं । उस पैरवी में किता खर्च आता है वह शायद आपको मालूम होगा क्योंकि आप गांव के हैं । उनके आने जाने के लिये कितना खर्चा देना पड़ता है, इस सब का तख्मीना आप लगाइये तो आपको पता चलेगा कि रुपया लेने वाला जितना प्राफिट करता है उस से ज्यादा खर्च पड़ जाता है । इस चीज को मैं मिड्ल मैन कहता हूं । साथ ही अब आप देखिये कि माइनर इरिगेशन के काम के लिये कितना दौड़ना पड़ता है। रुपया निकालने मे कितनी कठिनाई होती है इस का वर्णन पहले ही हो चुका है । मैं तो केवल इशारा करना चाहता था, लेकिन डिप्टी मिनिस्टर साहब चाहते थे कि मैं उसे खोल कर कहूं ।

इस रिपोर्ट पर मैंने पाया जो कि पेज २४ पर लिखा हुआ है :

"The number of persons trained so far is about 39,00,000."

३९ लाख लोगों की ट्रेनिंग हुई । हमारे यहां करीब साढ़े पांच लाख विलेजेज हैं । इस तरह से एक एक विलेजेज पर ७.७ आदमियों की ट्रेनिंग का हिसाब पड़ता है । यह लोग कहां गये, किधर गये, क्या करते हैं, कुछ मालूम नहीं है । उन पर रुपया खर्च हुआ । स्टेडी ऐंड अप्रिएन्टेशन आफ नान आफिशल्स के बारे में यह लिखा है । लेकिन वे लोग कहां गये ? किस विलेज में हैं ।

मैं यह जानना चाहता था कि ये लोग कहां गए और उनकी ट्रेनिंग पर जो रुपया खर्च हुआ वह कितना काम आ सका ।

दूसरी बात यह कि जो रुपया खर्च किया गया उसका फिजिकल एचीवमेंट क्या हुआ । मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर से हमको फिगर मिलते हैं कि माइनर इरिगेशन पर इतना रुपया खर्च हुआ, वैल्स पर इतना खर्च हुआ । सरकारी अनुमान के अनुसार एक वैल पर पांच एकड़ जमीन पटाने का हिसाब है । लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जिस वैल में बोरिंग नहीं होता उससे एक एकड़ भी मुश्किल से पटता है । तो आपके हिसाब से तो एक वैल पर पांच एकड़ के हिसाब से सींचने की बात कह दी जाती है लेकिन वास्तव में कितनी सिंचाई होती है यह न आपकी रिपोर्ट में आता है और न मिनिस्टर साहब की स्पीच में । मिनिस्ट्री आफ एग्रीकल्चर और मिनिस्ट्री आफ कम्युनिटी डेवेलपमेंट इतनी मिली हुई हैं कि इन में से किसी भी मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आती है उससे दूसरी मिनिस्ट्री का भी आभास मिल जाता है ।

कोआपरेटिव के बारे में और लोगों ने भी कहा है । हम लोग जब गांव में कोआपरेटिव का काम शुरू करना चाहते हैं तो पैसा खर्च कर तथा दौड़ दौड़ कर थक जाते हैं लेकिन कोआपरेटिव सोसाइटी नहीं बन पाती । तो ला और प्रोसीज्योर का ऐसा सिम्पलीफिकेशन होना चाहिए कि बिना बहुत दौड़े कोआपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाए । इतना इन्तिजाम आप कर दें तो लोगों का ज्यादा उपकार होगा बनिस्बत ज्यादा रुपया खर्च करने के ।

मेरा यह अनुभव है और शायद मिनिस्टर साहब भी जानते होंगे कि सरविस कोआपरेटिव कायम करने में कितनी दिक्कत आती है । जो कोआपरेटिव सोसाइटीज काम कर रही हैं, मेरा अपना अनुभव यह है कि उनमें से ५० प्रतिशत बेकार हैं, उनके पास साधन नहीं हैं और उन पर तवज्जह भी नहीं दी जाती । आप जानते हैं कि हमारे गांव के लोग सीधे सादे हैं । जब तक उनके साथ दलाल नहीं लग जाता वे पैरवी नहीं

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

कर सकते और जब दलाल उनके साथ लग जाता है तो उनको जो मिलता है उसमें से एक चौथाई रकम तो उड़ ही जाती है । तो अगर कानून में सिम्पलीफिकेशन हो तो कोआपरेटिव मूवमेंट से ज्यादा फायदा हो सकता है । और जितनी आज साधारण कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं उनको मल्टी परपज कोआपरेटिवस आप कर दें तो ज्यादा फायदा हो ।

शुगर केन कोआपरेटिव्स जो हैं उनको तो फी मन एक पैसा या दो पैसा मन कमीशन मिल जाता है और इसलिये उनके पास कुछ साधन हो जाता है । लेकिन जो आरडिनरी कोआपरेटिव्स हैं उनको कोई आमदनी नहीं है । वह रुपया लाती हैं और लोगों को देती हैं और उनको एक आध पर सेंट जो मिलता है वह खर्च के लिये भी काफी नहीं होता । अगर उनको मल्टी परपज कर दिया जाए और उनके द्वारा कोई छोटा उद्योग धन्धा या व्यापार चलाया जाए तो उनका भी काम चल सकता है ।

कुछ जमाने पहले हमने पढ़ा था कि हर एक ब्लाक डेवेलपमेंट लेविल पर गोबर का गैस प्लांट दिया जाएगा । लेकिन पता नहीं वह कितने बनें, कितने लोगों को दिये गये और कितने सफल हुए । वह किस कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक में गए इसका भी पता नहीं .....

अध्यक्ष महोदय : मुझे फिर आपका ध्यान इधर दिलाना पड़ेगा ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : तो मैं कह रहा था कि मवेशी के गोबर का जो गैस प्लांट निकला है उसका डिस्ट्रिब्यूशन कम्युनिटी डेवेलपमेंट ब्लाक्स में होने वाला था । लेकिन वह हम लोगों की तरफ नहीं गया है । हमने सुना कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होने वाला है । अगर वह इम्प्रूवमेंट होकर आ जाए तो उससे कुछ लोगों का उपकार हो सकता है और कुछ काम चल सकता है ।

तीसरी बात जो आपके सामने रखनी है वह यह है कि दस वर्षों से गांवों में कम्युनिटी डेवेलपमेंट का काम चल रहा है । उससे क्या फायदा हुआ इसके भी आंकड़े होने चाहिए जो कि नहीं हैं । जिन गांवों में यह काम किया गया है उनमें कितनी इन डेटेडनेस कम हुई और कितने लोग अपने पैरों पर खड़े हुए और कितने गांवों में कुछ काम सफल हुआ इसका कोई तखमीना नहीं है । तो मैं चाहूंगा कि इन सब बातों का विवरण मिनिस्टर साहब दें ताकि लोगों की समझ में सही बात आ सके । नहीं तो बहुत से लोगों का खयाल है कि कम्युनिटी डेवेलपमेंट के होने से सिर्फ कुछ आफिसेज खुल गये हैं और कुछ लोगों की परवस्ती हो रही है लेकिन असल काम नहीं हो रहा है । हालांकि इसका ध्येय अच्छा है लेकिन काम करने के तरीके ऐसे नहीं हैं जिससे लोगों को अधिक फायदा हो सके और खास कर ऐसे लोगों को जो कि गरीब हैं और जिनके पास न जमीन है और न कोई और साधन है उनको कर्ज मिल सके ।

मैं इन्हीं बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था ।

11·17 hours.

CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

SITUATION IN EAST PAKISTAN AND INCIDENTS AT MALDA

Mr. Speaker: I must refer to the notices of calling attention that have